

आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर
श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य एवं श्री विक्रम सिंह यादव, लेखा सदस्य के समक्ष

आयकर अपील सं. 342/JP/2017
निर्धारण वर्ष: 2014-15

Income-tax Officer Ward-1(2), Kota	बनाम	M/s Bagherwal Associates, Plot No. 1-B, Rajeev Gandhi Nagar, Kota
स्थायी लेखा सं./जीआईआर सं. AAMFB4305K		
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी

राजस्व की ओर से : श्रीमती रेशन्ता मीणा (जेसीआईटी)

निर्धारिती की ओर से : श्री सौरव हर्ष (अधिवक्ता)

सुनवाई की तारीख: 24/08/2018

उदघोषणा की तारीख: 29/08/2018

आदेश

श्री विक्रम सिंह यादव, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 हेतु आयकर आयुक्त (अपील), कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/12/2017 के विरुद्ध निर्देशित, राजस्व विभाग की वर्तमान अपील में उठाया गया हैं।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने कर प्रभाव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र संख्या 3/2018, दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसार, रुपये 20 लाख से अधिक न होने के कारण राजस्व की अपील की पोषणीयता पर आपत्ति उठाई। विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, राजस्व की अपील में रुपये 53,94,462/- की अभिवृद्धि पर रूपए 16,66,889/- का कर प्रभाव होने का उल्लेख किया गया है जो कि रूपए 20 लाख की निर्धारित सीमा से कम है।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि राजस्व की अपील में संबंधित कर प्रभाव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इसके पूर्ववर्ती परिपत्र संख्या, 21/2015,

दिनांक 10.12.2015 को निरस्त करते हुए जारी किए गए पश्चातवर्ती परिपत्र संख्या 3/2018, दिनांक 11 जुलाई 2018 में निर्धारित की गई सीमा रूपए 20 लाख से कम है।

4. हमने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। यह पाया गया कि राजस्व की प्रश्नगत अपील में मांग/कर प्रभाव रूपये 20 लाख से कम है। आयकर अधिनियम की धारा 268 ए (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में परिपत्र संख्या 3/2018, दिनांक 11 जुलाई 2018 (फा.संख्या.279/प्रकीर्ण.142/2007-आईटीजे (पीटी) द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों को यह निदेश जारी किए गए हैं कि ऐसी अपीलों, जिनमें मांग/कर प्रभाव रूपये 20 लाख तक सीमित हो, के मामलों में राजस्व विभाग द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल नहीं की जाएं। उक्त परिपत्र में इसके सभी लंबित अपीलों में प्रयोजनीय होने का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है।

5. कुछ अपवादों को छोड़कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह निदेश दिया है कि आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित ऐसी सभी विभागीय अपीलों, जिनमें मांग/कर प्रभाव रूपये 20 लाख से अधिक नहीं है, को या तो वापस ले लिया जाना चाहिए अथवा विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा उन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

6. वर्तमान अपील केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के उक्त परिपत्र में उल्लिखित अपवादों में से किसी ने से भी आच्छादित नहीं होती। क्योंकि वर्तमान विभागीय अपील में विवादास्पद कर मांग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अपील दाखिल किए हेतु निर्धारित सीमा से कम है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र संख्या 3/2018, दिनांक 11 जुलाई 2018 के प्रकाश में राजस्व की अपील पोषणीय नहीं है। तदानुसार, अपील पर जोर नहीं दिया जाना/ अपील को वापस लिया जाना मानते हुए विभाग की अपील को निरस्त किया जाता है।

7. परिणामस्वरूप, राजस्व की अपील निरस्त की जाती है।

आदेश दिनांक 29/08/2018 को न्यायालय में सार्वजनिक रूप से उद्घोषित किया गया।

Sd/-

(विजय पाल राव)
न्यायिक सदस्य

Sd/-

(विक्रम सिंह यादव)
लेखा सदस्य

जयपुर

दिनांक- 29th अगस्त, 2018

*Ganesh Kumar

आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी
3. आयकर आयुक्त
4. आयकर आयुक्त
5. विभागीय प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर
6. गार्ड फाईल (आयकर अपील सं. 342/JP/2018)

आदेशानुसार

सहायक पंजीकार